

## विचार बिन्दु

सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो किन्तु किसी को दुःख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। - भगवान श्रीकृष्ण

## इन्टरनेट के बादशाह पढ़ाई में फिसड्डी

भारत सरकार ने गत तीन दशकों से लंबित शिक्षा नीति 2020 को अंतिम रूप दे कर लागू कर दिया है। वस्तुतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में राष्ट्र निर्माण की दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं उनमें नई शिक्षा नीति एक अत्याधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य आगामी वर्षों में सबसे युवा देश को सही दिशा प्रदान करने वाला एवं नई वैश्विक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा ऐसी रणनीति है। आज जबकि विश्व बड़ी तेजी से बदल रहा है। ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटरीकरण और तकनीकी में नित नए प्रयोगों तथा नवोन्मेषी अनुसंधानों ने ज्ञान की दिशा ही बदल दी है। आज मनुष्य उस स्थान पर खड़ा है जहाँ से उसे बेतहासा दौड़ लगानी है। वैश्विक परिस्थितियां भूखे शेर की तरह आपका पीछा कर रही हैं। यदि आप पीछे रह जाँगे तो पराजय निश्चित है। यहाँ तक कि जीवित रहने के लिये भी आज हमें ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्वस्तरीय होना होगा अत्यावश्यक होगा है वर्ना जो भी इसमें पिछड़ जाएगा वे ही अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएँगे।

नई शिक्षा नीति ने इन्हीं मुद्दों को आधार बना कर तैयार की गई है। आने वाले वर्षों में हमारे सम्मुख आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रख कर तैयार की गई यह शिक्षा नीति राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर चुकी है।

हमारा शिक्षा का अतीत बहुत आश्चर्यजनक नहीं रहा था उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता में इतना पतन हो चुका है कि वैश्विक स्तर पर हम बहुत पिछड़े नजर आ रहे हैं। शिक्षा में इसी गुणवत्ता को नई शिक्षा नीति में प्रमुखता दी है।

शिक्षा में गुणवत्ता के प्रश्न पर काफी चर्चा परिचर्चा होती रही है परन्तु इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नई शिक्षा नीति में सुधार करते हुए न केवल 360 डिग्री मूल्यांकन, बल्कि शिक्षकों के ज्ञान और योग्यता की परख व उसमें सुधार जैसे बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। इसमें नवीन एवं प्राचीन का सन्तुलन: नए ज्ञान, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी व नवोन्मेषी तकनीकी के साथ-साथ नई हमारे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान तथा दर्शन को सहेजने व उस पर गहन अध्ययन एवं शोध को भी महत्व दिया गया है। इसलिये चिंतन के धरातल पर यह नई शिक्षा नीति संस्था नई है। वर्तमान सरकार की नीति "सबका साथ सबका विकास" के मूल सिद्धान्त है उस को नई शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है। अतः वंचित व उपेक्षित समाज के बच्चों के शैक्षणिक विकास के विभिन्न पहलुओं को भी इस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है साथ ही दिवांगजनों के विकास हेतु पर्याप्त प्रावधान हैं।

लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था प्रथम ने जो नवीनतम रिपोर्ट 2023 जारी की है उससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा के विपरीत है शिक्षकों का रवैया बेहद निराशाजनक ही नहीं गैर जिम्मेदाराना भी है।सर्वे में बदहाल शिक्षा का खुलासा करते हुए कहा गया है कि एक-चौथाई बच्चे नहीं दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ताजा वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर में देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर चौंकारे वाले आंकड़े सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 14 से 18 साल की उम्र के लगभग 26 प्रतिशत बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा 2 के स्तर का पाठ्यक्रम भी ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बच्चे स्कूल की दहलीज से लगभग बाहर आ चुके हैं। सोचिए वे कौन शिक्षक थे जो खानापूर्ति कर रहे थे। उनकी आत्मा ने यह जीवित मक्खी कैसे निगली होगी। स्मरण रहे प्राथमिक शिक्षा को हम नींव कहते हैं तो क्या हमारे गुरुजान गामा गिरा भर रहे हैं देश के भविष्य की इमारत में। इसी आयु वर्ग में कम से कम 42 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। अब अंग्रेजी की हालत तो खुद गुरुओं की ही खराब है बच्चों की क्या कहेंगे।क्योंकि न हो तो राजस्थान में खोले गए अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों का परीक्षण कर लीजिए।

इस कमजोर बुनियाद का असर यह हो रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ ये बच्चे स्कूल-कॉलेज से दूर हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 14-18 साल के कुल 86.8 प्रतिशत बच्चों ने स्कूल या कॉलेज में दाखिला ले रखा है अर्थात् लगभग 14 बच्चे बाहर हैं इसके साथ ही की जैसे-जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे स्कूल-कॉलेज में इनका नामांकन भी कम होने लग जाता है। फिलहाल स्कूल या कॉलेज में दाखिला नहीं लेने वाले 14 साल तक के बच्चों का आंकड़ा 3.9 प्रतिशत है। 16 साल के बच्चों में ये आंकड़ा 10.9 प्रतिशत और 18 साल के बच्चों में 32.6 प्रतिशत तक है।

गणितशिक्षा के समाचार सबसे बुरे हैं। जबकि अच्छे तकनीकी के जानकारों के लिए गणित एक अपरिहार्य विषय है। गणित में 2017 में 14-18 साल के 76.6 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ सकते थे, जबकि 2023 में ये आंकड़ा घटकर होकर 73.6 प्रतिशत पर आ गया है। आधे से अधिक छात्र 3 और एक अंक की संख्या के विभाजन को ही हल नहीं कर पा रहे हैं। रपट खुलासा करती है कि 76 प्रतिशत छात्राएँ अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा दूसरी के स्तर का पाठ आसानी से पढ़ ले रही हैं। छात्रों में ये आंकड़ा 70.9 प्रतिशत है।इसके उलट छात्र अंकगणित और अंग्रेजी पाठ पढ़ने में छात्राओं से बेहतर हैं।विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टीम में प्रवेश करने वाले बच्चों में फिसड्डी यह पीढ़ी स्मार्ट फोन की जरूर मास्टर बन रही है। दिखने में यह विरोधाभास प्रतीत हो रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है। दरसअल यह पीढ़ी स्मार्ट फोन का इस्तेमाल गैर जरूरी काम में कर रही है जिसका अधिकांश हिस्सा मनोरंजन, और सोसियल मीडिया और विडिओ गेम्स से जुड़ा है। स्मार्टफोन तक छात्रों की पहुंच ज्यादा गया है कि लगभग 89 प्रतिशत छात्रों के घर में स्मार्टफोन है। इनमें से 92 प्रतिशत इसे चलाना भी जानते हैं और 31 प्रतिशत के पास खुद का स्मार्टफोन है।स्मार्टफोन तक पहुंच के मामले में छात्राएँ काफी पीछे हैं। जिन 31 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास खुद का स्मार्टफोन है, उनमें से 43.7 प्रतिशत छात्र और 19.8 प्रतिशत छात्राएँ हैं। स्मार्टफोन तक पहुंच वाले 90.5 प्रतिशत विद्यार्थी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। प्रथम फांडेडेशन ने यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए 26 राज्यों में सरकारी और निजी संस्थानों में नामांकित 34,745 युवाओं का सर्वे किया। इस बार सर्वे केवल 14 से 18 साल के विद्यार्थियों पर किया गया था।

2022 में स्कूली बच्चों पर लॉकडाउन के प्रभावों को समझने के लिए 616 जिलों के 19,060 स्कूलों के लगभग 7 लाख बच्चों पर सर्वे किया गया था। ये सर्वे हर दो साल में किया जाता है। सर्वे की यह रिपोर्ट सन्मुख डरावनी है। नई शिक्षा नीति की सफलता केवल नए पाठ्यक्रमों, शिक्षक प्रशिक्षणों और भारी धन निवेश के जरिए सम्भव नहीं है। जबतक शिक्षकों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसी दुर्घटनाओं का क्रम अनवरत जारी रहेगा। आप ही सोचिए अगर 14से18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे पिछड़ जाएंगे तो राष्ट्र कैसे सम्भलेगा कैसे संवरेगा। इस मुद्दे पर तत्काल कारगर कदम उठाने ही पड़ेंगे अब हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

- राजेश्वर मोहन शर्मा  
अतिथि सम्पादक

शिक्षाविद, साहित्यकार और चिन्तक

शिक्षा में गुणवत्ता के प्रश्न पर काफी चर्चा परिचर्चा होती रही है परन्तु इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नई शिक्षा नीति में सुधार करते हुए न केवल 360 डिग्री मूल्यांकन, बल्कि शिक्षकों के ज्ञान और योग्यता की परख व उसमें सुधार जैसे बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। इसमें नवीन एवं प्राचीन का सन्तुलन: नए ज्ञान, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी व नवोन्मेषी तकनीकी के साथ-साथ नई हमारे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान तथा दर्शन को सहेजने व उस पर गहन अध्ययन एवं शोध को भी महत्व दिया गया है। इसलिये चिंतन के धरातल पर यह नई शिक्षा नीति सर्वथा नई है। वर्तमान सरकार की नीति "सबका साथ सबका विकास" के मूल सिद्धान्त है उस को नई शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है। अतः वंचित व उपेक्षित समाज के बच्चों के शैक्षणिक विकास के विभिन्न पहलुओं को भी इस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है साथ ही दिवांगजनों के विकास हेतु पर्याप्त प्रावधान हैं।

लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था प्रथम ने जो नवीनतम रिपोर्ट 2023 जारी की है उससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा के विपरीत है शिक्षकों का रवैया बेहद निराशाजनक ही नहीं गैर जिम्मेदाराना भी है।सर्वे में बदहाल शिक्षा का खुलासा करते हुए कहा गया है कि एक-चौथाई बच्चे नहीं दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ताजा वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर में देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर चौंकारे वाले आंकड़े सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 14 से 18 साल की उम्र के लगभग 26 प्रतिशत बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा 2 के स्तर का पाठ्यक्रम भी ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बच्चे स्कूल की दहलीज से लगभग बाहर आ चुके हैं। सोचिए वे कौन शिक्षक थे जो खानापूर्ति कर रहे थे। उनकी आत्मा ने यह जीवित मक्खी कैसे निगली होगी। स्मरण रहे प्राथमिक शिक्षा को हम नींव कहते हैं तो क्या हमारे गुरुजान गामा गिरा भर रहे हैं देश के भविष्य की इमारत में। इसी आयु वर्ग में कम से कम 42 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। अब अंग्रेजी की हालत तो खुद गुरुओं की ही खराब है बच्चों की क्या कहेंगे।क्योंकि न हो तो राजस्थान में खोले गए अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों का परीक्षण कर लीजिए।

इस कमजोर बुनियाद का असर यह हो रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ ये बच्चे स्कूल-कॉलेज से दूर हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 14-18 साल के कुल 86.8 प्रतिशत बच्चों ने स्कूल या कॉलेज में दाखिला ले रखा है अर्थात् लगभग 14 बच्चे बाहर हैं इसके साथ ही की जैसे-जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे स्कूल-कॉलेज में इनका नामांकन भी कम होने लग जाता है। फिलहाल स्कूल या कॉलेज में दाखिला नहीं लेने वाले 14 साल तक के बच्चों का आंकड़ा 3.9 प्रतिशत है। 16 साल के बच्चों में ये आंकड़ा 10.9 प्रतिशत और 18 साल के बच्चों में 32.6 प्रतिशत तक है।

गणितशिक्षा के समाचार सबसे बुरे हैं। जबकि अच्छे तकनीकी के जानकारों के लिए गणित एक अपरिहार्य विषय है। गणित में 2017 में 14-18 साल के 76.6 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ सकते थे, जबकि 2023 में ये आंकड़ा घटकर होकर 73.6 प्रतिशत पर आ गया है। आधे से अधिक छात्र 3 और एक अंक की संख्या के विभाजन को ही हल नहीं कर पा रहे हैं। रपट खुलासा करती है कि 76 प्रतिशत छात्राएँ अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा दूसरी के स्तर का पाठ आसानी से पढ़ ले रही हैं। छात्रों में ये आंकड़ा 70.9 प्रतिशत है।इसके उलट छात्र अंकगणित और अंग्रेजी पाठ पढ़ने में छात्राओं से बेहतर हैं।विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टीम में प्रवेश करने वाले बच्चों में फिसड्डी यह पीढ़ी स्मार्ट फोन की जरूर मास्टर बन रही है। दिखने में यह विरोधाभास प्रतीत हो रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है। दरसअल यह पीढ़ी स्मार्ट फोन का इस्तेमाल गैर जरूरी काम में कर रही है जिसका अधिकांश हिस्सा मनोरंजन, और सोसियल मीडिया और विडिओ गेम्स से जुड़ा है। स्मार्टफोन तक छात्रों की पहुंच ज्यादा गया है कि लगभग 89 प्रतिशत छात्रों के घर में स्मार्टफोन है। इनमें से 92 प्रतिशत इसे चलाना भी जानते हैं और 31 प्रतिशत के पास खुद का स्मार्टफोन है।स्मार्टफोन तक पहुंच के मामले में छात्राएँ काफी पीछे हैं। जिन 31 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास खुद का स्मार्टफोन है, उनमें से 43.7 प्रतिशत छात्र और 19.8 प्रतिशत छात्राएँ हैं। स्मार्टफोन तक पहुंच वाले 90.5 प्रतिशत विद्यार्थी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। प्रथम फांडेडेशन ने यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए 26 राज्यों में सरकारी और निजी संस्थानों में नामांकित 34,745 युवाओं का सर्वे किया। इस बार सर्वे केवल 14 से 18 साल के विद्यार्थियों पर किया गया था।

2022 में स्कूली बच्चों पर लॉकडाउन के प्रभावों को समझने के लिए 616 जिलों के 19,060 स्कूलों के लगभग 7 लाख बच्चों पर सर्वे किया गया था। ये सर्वे हर दो साल में किया जाता है। सर्वे की यह रिपोर्ट सन्मुख डरावनी है। नई शिक्षा नीति की सफलता केवल नए पाठ्यक्रमों, शिक्षक प्रशिक्षणों और भारी धन निवेश के जरिए सम्भव नहीं है। जबतक शिक्षकों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसी दुर्घटनाओं का क्रम अनवरत जारी रहेगा। आप ही सोचिए अगर 14से18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे पिछड़ जाएंगे तो राष्ट्र कैसे सम्भलेगा कैसे संवरेगा। इस मुद्दे पर तत्काल कारगर कदम उठाने ही पड़ेंगे अब हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

- राजेश्वर मोहन शर्मा  
अतिथि सम्पादक

शिक्षाविद, साहित्यकार और चिन्तक

शिक्षा में गुणवत्ता के प्रश्न पर काफी चर्चा परिचर्चा होती रही है परन्तु इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नई शिक्षा नीति में सुधार करते हुए न केवल 360 डिग्री मूल्यांकन, बल्कि शिक्षकों के ज्ञान और योग्यता की परख व उसमें सुधार जैसे बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। इसमें नवीन एवं प्राचीन का सन्तुलन: नए ज्ञान, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी व नवोन्मेषी तकनीकी के साथ-साथ नई हमारे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान तथा दर्शन को सहेजने व उस पर गहन अध्ययन एवं शोध को भी महत्व दिया गया है। इसलिये चिंतन के धरातल पर यह नई शिक्षा नीति संस्था नई है। वर्तमान सरकार की नीति "सबका साथ सबका विकास" के मूल सिद्धान्त है उस को नई शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है। अतः वंचित व उपेक्षित समाज के बच्चों के शैक्षणिक विकास के विभिन्न पहलुओं को भी इस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है साथ ही दिवांगजनों के विकास हेतु पर्याप्त प्रावधान हैं।

लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था प्रथम ने जो नवीनतम रिपोर्ट 2023 जारी की है उससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा के विपरीत है शिक्षकों का रवैया बेहद निराशाजनक ही नहीं गैर जिम्मेदाराना भी है।सर्वे में बदहाल शिक्षा का खुलासा करते हुए कहा गया है कि एक-चौथाई बच्चे नहीं दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ताजा वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर में देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर चौंकारे वाले आंकड़े सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 14 से 18 साल की उम्र के लगभग 26 प्रतिशत बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा 2 के स्तर का पाठ्यक्रम भी ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बच्चे स्कूल की दहलीज से लगभग बाहर आ चुके हैं। सोचिए वे कौन शिक्षक थे जो खानापूर्ति कर रहे थे। उनकी आत्मा ने यह जीवित मक्खी कैसे निगली होगी। स्मरण रहे प्राथमिक शिक्षा को हम नींव कहते हैं तो क्या हमारे गुरुजान गामा गिरा भर रहे हैं देश के भविष्य की इमारत में। इसी आयु वर्ग में कम से कम 42 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। अब अंग्रेजी की हालत तो खुद गुरुओं की ही खराब है बच्चों की क्या कहेंगे।क्योंकि न हो तो राजस्थान में खोले गए अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों का परीक्षण कर लीजिए।

इस कमजोर बुनियाद का असर यह हो रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ ये बच्चे स्कूल-कॉलेज से दूर हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 14-18 साल के कुल 86.8 प्रतिशत बच्चों ने स्कूल या कॉलेज में दाखिला ले रखा है अर्थात् लगभग 14 बच्चे बाहर हैं इसके साथ ही की जैसे-जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे स्कूल-कॉलेज में इनका नामांकन भी कम होने लग जाता है। फिलहाल स्कूल या कॉलेज में दाखिला नहीं लेने वाले 14 साल तक के बच्चों का आंकड़ा 3.9 प्रतिशत है। 16 साल के बच्चों में ये आंकड़ा 10.9 प्रतिशत और 18 साल के बच्चों में 32.6 प्रतिशत तक है।

गणितशिक्षा के समाचार सबसे बुरे हैं। जबकि अच्छे तकनीकी के जानकारों के लिए गणित एक अपरिहार्य विषय है। गणित में 2017 में 14-18 साल के 76.6 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ सकते थे, जबकि 2023 में ये आंकड़ा घटकर होकर 73.6 प्रतिशत पर आ गया है। आधे से अधिक छात्र 3 और एक अंक की संख्या के विभाजन को ही हल नहीं कर पा रहे हैं। रपट खुलासा करती है कि 76 प्रतिशत छात्राएँ अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा दूसरी के स्तर का पाठ आसानी से पढ़ ले रही हैं। छात्रों में ये आंकड़ा 70.9 प्रतिशत है।इसके उलट छात्र अंकगणित और अंग्रेजी पाठ पढ़ने में छात्राओं से बेहतर हैं।विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टीम में प्रवेश करने वाले बच्चों में फिसड्डी यह पीढ़ी स्मार्ट फोन की जरूर मास्टर बन रही है। दिखने में यह विरोधाभास प्रतीत हो रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है। दरसअल यह पीढ़ी स्मार्ट फोन का इस्तेमाल गैर जरूरी काम में कर रही है जिसका अधिकांश हिस्सा मनोरंजन, और सोसियल मीडिया और विडिओ गेम्स से जुड़ा है। स्मार्टफोन तक छात्रों की पहुंच ज्यादा गया है कि लगभग 89 प्रतिशत छात्रों के घर में स्मार्टफोन है। इनमें से 92 प्रतिशत इसे चलाना भी जानते हैं और 31 प्रतिशत के पास खुद का स्मार्टफोन है।स्मार्टफोन तक पहुंच के मामले में छात्राएँ काफी पीछे हैं। जिन 31 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास खुद का स्मार्टफोन है, उनमें से 43.7 प्रतिशत छात्र और 19.8 प्रतिशत छात्राएँ हैं। स्मार्टफोन तक पहुंच वाले 90.5 प्रतिशत विद्यार्थी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। प्रथम फांडेडेशन ने यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए 26 राज्यों में सरकारी और निजी संस्थानों में नामांकित 34,745 युवाओं का सर्वे किया। इस बार सर्वे केवल 14 से 18 साल के विद्यार्थियों पर किया गया था।

2022 में स्कूली बच्चों पर लॉकडाउन के प्रभावों को समझने के लिए 616 जिलों के 19,060 स्कूलों के लगभग 7 लाख बच्चों पर सर्वे किया गया था। ये सर्वे हर दो साल में किया जाता है। सर्वे की यह रिपोर्ट सन्मुख डरावनी है। नई शिक्षा नीति की सफलता केवल नए पाठ्यक्रमों, शिक्षक प्रशिक्षणों और भारी धन निवेश के जरिए सम्भव नहीं है। जबतक शिक्षकों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसी दुर्घटनाओं का क्रम अनवरत जारी रहेगा। आप ही सोचिए अगर 14से18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे पिछड़ जाएंगे तो राष्ट्र कैसे सम्भलेगा कैसे संवरेगा। इस मुद्दे पर तत्काल कारगर कदम उठाने ही पड़ेंगे अब हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

- राजेश्वर मोहन शर्मा  
अतिथि सम्पादक

शिक्षाविद, साहित्यकार और चिन्तक



डॉ. अमित वर्मा

भगवान श्रीराम के जीवन का संदेश हमें यह सिखाता है कि धरती पर आने का मतलब सत्य, न्याय और प्रेम का पालन करना है। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के इस पवित्र अवसर पर हम सभी मिलकर श्रीराम के अद्वितीय चरित्र की महिमा को याद करते हुए उनके आदर्शों का पालन करने का संकल्प लेंगे।

राम नाम के हीरो मोती मैं बिकराऊं गली-गली। लो-लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली-गली। भगवान राम को समर्पित यह प्रसिद्ध भजन हमारे मन को बहुत आनंद देता है। राम नाम ही अपने आप में सर्वोत्तम है। राम का नाम लेने से सारी पीड़ाएँ और कष्ट कम हो जाते हैं। भगवान राम जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, वह पूरे संसार के

पालनहार हैं। भगवान राम का नाम जगत में सारी पीड़ा को हरने वाला है। भगवान राम को आदर्शवादी महान राजा और एक अच्छे पुत्र के व्यक्तित्व को आज भी याद किया जाता है। संत तुलसीदास ने रामचंद्र जी के गुणों का बखान अपने अनेक दोहों में किया है। 22 जनवरी, 2024 को बरसों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर में रामलला पधारंगे। ये भव्य दृश्य देखने के लिए प्रत्येक सनातनी और हिंदू का मन भी यकीनन ललचा रहा होगा। आखिर उनके स्वागत में सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत जश्न मना रहा है, चारों ओर राजा राम के नाम की गूंज है। हो भी क्यों ना, बरसों के वनवास के बाद सबके दुलारे राजा राम अपने धाम में विराजेंगे। अयोध्या में रामलला का स्वागत जोर-शोर से करने के लिए विदेशों तक निमंत्रण भेजा गया है। भगवान श्रीराम, जिन्हें सर्वशक्तिमान के रूप में पूजा जाता है, वे आदर्श मानवता के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन के अनेक पहलुओं ने हमें यह सिखाया है कि कैसे सत्य, न्याय, और प्रेम का पालन करके हम सभी एक उच्च और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।

राम मंदिर उद्घाटन से पहले आइए जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के जीवन के कुछ खास और अनसुने किस्से, जिनसे हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रामलला अयोध्या आएंगे तो 22 जनवरी को ही देश में हम सभी

मिलकर दिवाली मनाएँगे। सत्य और न्याय के पुजारी रामलला को अपने जीवन में विभिन्न परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धरती पर आए राम के रूप में अपनी भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रखा है।

भगवान राम के जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। हिंदू शास्त्र में एक से बढ़कर एक महान गुरु शिक्षक रहे हैं। वहाँ धर्म के मार्ग पर चलने वाले भगवान राम ने भी गुरु से शिक्षा प्राप्त की और उन्हीं के मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाया। गुरु के बिना भगवान राम कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते। जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। गुरु का महत्व आज से ही नहीं, बल्कि पुराने समय से ही सर्वोपरि रहा है। गुरु को हमेशा भगवान का दर्जा दिया गया है। व्यक्ति को माता-पिता के बाद जो भी कुछ सिखाया जाता है, वह गुरु द्वारा ही सिखाया जाता है। आम व्यक्ति ही नहीं भगवान भी गुरु में समर्पित रहे हैं।

भगवान श्रीराम ने ऋषि विश्व, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भारद्वाज व ब्रह्मिष् अगस्त्य के शिष्य के रूप में अपनी समस्त शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्रीराम को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। भगवान राम को परम योद्धा बनाने के पीछे विश्वामित्र ही थे। भगवान राम के पास जितने भी दिव्य शास्त्र थे, वे सब विश्वामित्र के

ही दिए हुए थे। हिंदू शास्त्र के अनुसार महर्षि विश्वामित्र को त्रेता युग का सबसे बड़ा आयुध आविष्कारक माना जाता है। वहीं ऋषि विश्व ने भगवान राम को राजपाट संभालने का ज्ञान दिया था। इसके साथ ही वेदों की भी शिक्षा ऋषि विश्व ने ही भगवान राम को दी थी। यही नहीं, भगवान राम का राष्ट्राभिषेक भी ऋषि विश्व के हाथों ही हुआ था। ऋषि विश्व का भगवान राम के जीवन में विशेष महत्व है।

वहीं महर्षि भारद्वाज ने भगवान राम को विमान का ज्ञान दिया था। भारद्वाज ऋग्वेद के छठे मंडल के ऋषि रूप में विख्यात हैं। रामायण के अनुसार, भगवान श्रीराम ने महर्षि भारद्वाज के से ही परामर्श पर वनवास की अवधि में किचकट में वास किया था। लंका विजय के उपरांत लौटते समय भी भगवान राम इनके आश्रम में रुके थे। भगवान राम के जीवन में ब्रह्मिष् अगस्त्य का भी विशेष महत्व है। ब्रह्मिष् अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। रामायण के अनुसार, रावण के साथ युद्ध करते हुए जब राम थक जाते हैं और हताश होकर बैठ गए थे, तब ब्रह्मिष् अगस्त्य ने ही उनका हौसला बढ़ाया था।

भगवान श्रीराम ने अपने गुरुओं को प्रेरणास्त्रोत रखने के साथ ही अपने आदर्शों के माध्यम से भी हमें सिखाया है कि कैसे हमें अपने जीवन में सच्चाई और सही मार्ग का पालन करना चाहिए। उनका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि चुनौतियों का

सामना करते हुए भी हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए और आदर्शों के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके आदर्शों का पालन करेंगे और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों को अपनी जिंदगी में अपनाएँगे। विपत्तियों का सामना करते हुए भी राम ने धरती पर आए रामलला का आभास दिलाया। उनके वचन सदा ही उनके भक्तों के दिलों में बसे रहते हैं।

रामलला की कथाएं हमें उनके अद्वितीय चरित्र के प्रति आदर्श बनाती हैं और हमें सार्थक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। श्रीराम ने अपने अनुयायियों को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। उनके वचन सत्य ही शिक्षक हैं, जिन्होंने अनगिनत लोगों के दिलों को छू लिया है। आज हम सभी भक्त श्रीराम जी की पूजा-अर्चना में लिपटे हुए हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि धरती पर आने का मतलब सत्य, न्याय और प्रेम का पालन करना है। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के इस पवित्र अवसर पर हम सभी मिलकर श्रीराम के अद्वितीय चरित्र की महिमा को याद करते हुए उनके आदर्शों का पालन करने का संकल्प लेंगे। भगवान श्रीराम की कृपा हमें सदैव मिलती रहे। श्रय श्रीराम।

- डॉ. अमित वर्मा,  
मीडिया गुरु।

## कड़ाके की ठंड से शहद का उत्पादन प्रभावित, मधुमक्खी पालक परेशान

### हाइ कंपाने वाली ठंड का दौर निरंतर जारी रहने से शहद का उत्पादन घटा

हनुमानगढ़, (निर्स)। कड़ाके की ठंड ने एक तरफ जहाँ आमजन को प्रभावित कर रखा है, वहीं मधुमक्खी पालक भी जाड़े की चपेट में आ गए हैं। क्योंकि हाइ कंपाने वाली ठंड का दौर निरंतर जारी रहने से शहद का उत्पादन घट गया है। साथ ही पालकों को वाजिब दाम भी शहद के नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र के मधुमक्खी पालकों में बहुत हताशा है।

मधुक्रांति बीफार्मर्स वेलफेयर सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष ढाणी अराईयन निवासी प्रकाशसिंह बाल ने बताया कि सरसों में फूलों की बहार के चलते यह शहद उत्पादन का सीजन है। मगर कड़ाके की ठंड मधुमक्खियों पर आपत बन टूट रही है। इसका खमियाजा मधुमक्खी पालकों को आर्थिक नुकसान के रूप में झेलना पड़ रहा है। बादल ने बताया कि उनके पास 450 मधुमक्खी बॉक्स हैं। सीजन में एक बॉक्स से तकरीबन 25

### ठंड से मधुमक्खियों का मरना पालकों की अच्छे उत्पादन की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है

से 30 किलो शहद मिलता है। मगर इस बार मौसम का साथ नहीं मिलने से उत्पादन वमृशिकल 12 से 15 किलोग्राम ही होने के आसार हैं। धूप नहीं निकलने से मधुमक्खियां बाहर नहीं निकल पाती। यदि निकलती है तो सर्दी से मर जाती हैं। इससे शहद उत्पादन घटने के साथ-साथ उन्हें बॉक्स में ही कुत्रिम भोजन देना पड़ रहा है। इससे भी शहद उत्पादन का खर्च और बढ़ गया है। ठंड से मधुमक्खियों का मरना पालकों की अच्छे उत्पादन की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। मधुक्रांति बीफार्मर्स वेलफेयर

सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश सिंह ने बताया कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (एमईपी) लागू करने की गुहार केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र भेजकर लगाई है। मधुमक्खी पालकों का जीवन संकट से गुजर रहा है। इसका मुख्य कारण शहद उत्पादन का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। मौसम खराब होने के चलते शहद का उत्पादन लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक कम हो रहा है। इसके कारण मधुमक्खी पालक आर्थिक रूप से परेशान हैं। यदि समय रहते हालात नहीं सुधरे तो प्रधानमंत्री की प्रिय योजना स्वीट क्रांति संकट में पड़ जाएगा।

उद्यान विभाग हनुमानगढ़ के निदेशक साहबराग गोदारा का कहना है कि मधुमक्खी पालकों की एमईपी से संबंधित मांग का पत्र मिला था। उनकी यह मांग उद्यान आयुक्तलाय जयपुर के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी है।

## समर्थन मूल्य को वैधानिक मान्यता कब मिलेगी!

केन्द्र ने साल 2016 में डीफआई कमेटी का गठन किया और साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने एफरेली में देशभर के किसानों की आय दुगुनी करने की घोषणा की। देश में माहौल बनाया गया आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मानों किसानों का कायाकल्प होने वाला हो। एक तरफ आमदनी दुगुनी करने के किसानों को सबबगार दिखाये जा रहे थे तो दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से 3 कृषि कानून लाकर लागू करने की तैयारी हो रही थी। एक देश एक मण्डी के नाम पर बड़ा इवेंट बनाया गया। लेकिन किसानों ने सहजता से भांप लिया जमाखोरी की बंदिशें हटाकर और कंटेन्ट फार्मिंग के जरिये सरकार करिपोट के हाथों में खेती सौंपने की तैयारी कर रही है। देश में लम्बे समय तक चलने वाला बड़ा किसान आंदोलन हुआ किसानों के अथक और अडिग इरादों के आगे केन्द्र को युपी चुनाव सामने देख पीछे हटना पड़ा और किसान संघटनों और सरकार के बीच एमएसपी गारंटी,

किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने आदि का समझौता करने और माफ़ी देने पर प्रधानमंत्री की विश्वास होना पड़ा। लेकिन उक्त समझौते को लम्बा समय गुजर गया है लेकिन केन्द्र ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। जिसको लेकर किसान संगठन पुनः आंदोलन के लिए सक्रिय हो रहे हैं। आमदनी दुगुनी करने के दावे का सच जानने के लिए केन्द्र सरकार के संसद में दिये गये सवालों के जवाबों को टटोलने की आवश्यकता है। 23 जुलाई 2021 को राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सवाल पूछा गया। जिसके लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2015-16 में किसानों अनुमानित औसत आय 8,703 रुपये वार्षिक है। इस हिसाब से किसानों की मासिक औसत आय 8,058 रुपये हुई। इस मासिक आय के आधार पर सरकार के वायदे और टारगेट के अनुसार वर्ष 2022 में किसानों को मासिक आय 16,116 रुपये हो जानी चाहिये थी।

तो क्या ऐसा हो चुका है? 16 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में किसानों की आय के बारे में कृषि मंत्रालय से पुनः सवाल पूछा गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिसका लिखित जवाब दिया है। जिसके अनुसार देश के किसान की मासिक औसत आय 10,218 रुपये है। 5 साल में मात्र 2160 रूपये आमदनी बढ़ी यानी मोदी सरकार का आमदनी दुगुनी करने का वादा चुमला साबित हुआ। अभी हाल ही में संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट